Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 1, January-2022, ISSN 2230-7540

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

Rakesh Meena[1]*, Vikram Meena[2]

[1] Research Scholar, University of Rajasthan

[2] Research Scholar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur

*सार - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत के कृ ष और ग्रामीण वकास में महत्वपूर्ण भू मका निभाते हैं। आरआरबीएस अपने वशाल नेटवर्क के माध्यम से भारत के ग्रामीण इलाकों में अ धक पहुंच गया है। भारत में ग्रामीण ऋण की सफलता काफी हद तक उनकी वत्तीय ताकत पर निर्भर करती है। आरआरबी ग्रामीण स्तर पर प्रमुख वत्त पोषण संस्थान हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में व भन्न प्रकार के कृ ष ऋणों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। वर्तमान में, अ धकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अतिदेय, वसूली, गैर-निष्पादित आस्तियों और अन्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस लए, भारत में आरआरबी के वत्तीय प्रदर्शन का अध्ययन करना आवश्यक है। यह पेपर **2006-07** से **2010-2011** की अव ध के दौरान भारत में आरआरबी के वत्तीय प्रदर्शन का वश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन नाबार्ड और आरबीआई की वा र्षक रिपोर्ट से एकत्रित द् वतीयक डेटा पर आधारित है। वर्तमान अध्ययन में प्रमुख प्रदर्शन संकेतक वश्लेषण जैसे क बैंकों और शाखाओं की संख्या, जमा, ऋण, ऋण, निवेश और वकास दर सूचकांक का एक वश्लेषणात्मक अनुसंधान डजाइन का पालन कया जाता है। अध्ययन प्रकृति में नैदानिक और खोजपूर्ण है और द् वतीयक डेटा का उपयोग करता है। अध्ययन से पता चलता है और निष्कर्ष निकाला है क आरआरबी के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है।*

कीवर्ड - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक, वकास दर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था।

----------X----------

परिचय

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय वत्तीय परिदृश्य में लगभग 36 वर्षों से अस्तित्व में हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण की अत्य धक मांग को पूरा करने के लए बनाई गई थी, वशेष रूप से आ र्थक और सामाजिक रूप से हा शए पर रहने वाले वर्गों के बीच। बैं कंग आयोग (1972) ने ग्रामीण ऋण के लए एक वैकल्पिक संस्था स्था पत करने की सफारिश की और अंततः भारत सरकार ने एम. नर सम्हम की अध्यक्षता में कार्य समूह की सफारिशों के आधार पर मूल रूप से ग्रामीण ऋण के लए एक अलग संस्था के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। गरीबों को कम लागत वाली बैं कंग सु वधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लए, नर सम्हम व र्कंग ग्रुप (1975) ने संस्थानों के रूप में बैंकों के एक नए समूह की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो "स्थानीय अनुभव और ग्रामीण समस्याओं से परि चत हों, जो सहकारी स मतियों के पास हैं। और व्यापार संगठन की डग्री, जमारा श जुटाने की क्षमता, केंद्रीय मुद्रा बाजारों तक पहुंच और आधुनिक दृष्टिकोण जो वा णज्यिक बैंकों के पास है"।

इसके बाद, 1976 के आरआरबी अ धनियम की घोषणा के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। आरआरबी अ धनियम, 1976 वकासात्मक और पुन र्वतरण दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लए इस समग्र दृष्टि को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। आरआरबी की स्थापना "ग्रामीण क्षेत्रों में कृ ष, व्यापार, वा णज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गति व धयों के वकास के उद्देश्य से, वशेष रूप से छोटे और सीमांत कसानों को ऋण और अन्य सु वधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वक सत करने की दृष्टि से की गई थी।" खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्य मयों, और उससे जुड़े और प्रासं गक मामलों के लए "। उनकी इक्विटी क्रमशः 50:15:35 के अनुपात में केंद्र सरकार, संबं धत राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा

www.ignited.in

आयोजित की जाती है। इन ग्रामीण वत्तीय संस्थानों के जनादेश थे:

1. कंग को ग्रामीण जनता के दरवाजे तक ले जाना, वशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बैं कंग सु वधाएं नहीं हैं;

2. समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लए, इन बैंकों के एकमात्र ग्राहक कौन थे?

3. ग्रामीण बचत को जुटाना और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गति व धयों का समर्थन करने के लए उन्हें व्यवस्थित करना;

4. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना

5. ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की लागत को कम करना

साहित्य की समीक्षा

देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज और प्रदर्शन को देखने के लए कई अध्ययन कए गए हैं। भारत में आरआरबी के कामकाज और प्रदर्शन में उपलब्ध साहित्य थोड़ा सी मत है। केंद्र सरकार, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्था पत व भन्न स मतियों, आयोगों और कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट के रूप में जांचकर्ताओं द्वारा प्राप्त साहित्य, शोध अध्ययन, शोधकर्ताओं के लेख, बैंक अ धकारियों, अर्थशास्त्रियों और आ र्थक वश्लेषकों की टिप्प णयों और इस भाग में समाचार की सं क्षप्त समीक्षा की गई है। समीक्षाओं के कुछ संबं धत साहित्य इस प्रकार हैं।

केलकर स मति (1986) ने संगठनात्मक और परिचालन दोनों पहलुओं को शा मल करते हुए व्यापक सफारिशें कीं। इनमें से कई को आरआरबी अ धनियम, 1976 में संशोधन के रूप में शा मल कया गया था जैसे:

1. आरआरबी की अ धकृत पूंजी को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये और प्रदत्त शेयर पूंजी को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना;

2. नाबार्ड के परामर्श से संबं धत प्रायोजक बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष की नियुक्ति;

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके अस्तित्व के पहले पांच वर्षों में प्रायोजक बैंकों द्वारा आरआरबी कर्मचारियों के प्र शक्षण और आरआरबी को वत्तीय सहायता देने के लए अ धक मात्रा में सहायता का प्रावधान;

4. सभी संबं धत पक्षों के परामर्श से आरआरबी के समामेलन का प्रावधान।

5. प्रायोजक बैंकों को आरआरबी की प्रगति की निगरानी करने और उनके निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि की व्यवस्था करने के लए सशक्त बनाना।

हालां क कार्यान्वयन की प्रगति धीमी थी (संशो धत अ धनियम केवल सतंबर, 1988 के अंत तक लागू हुआ), इसमें सुधार की पर्याप्त गुंजाइश थी।

नाबार्ड (1986) ने "आरआरबी व्यवहार्यता पर एक अध्ययन" प्रका शत कया, जिसे नाबार्ड की ओर से 1986 में कृ ष वत्त निगम द्वारा संचा लत कया गया था। अध्ययन से पता चला क आरआरबी की व्यवहार्यता अनिवार्य रूप से फंड प्रबंधन रणनीति, संसाधनों की गतिशीलता और उनकी तैनाती के बीच मार्जिन और अ ग्रमों के साथ वर्तमान और भ वष्य की लागतों पर नियंत्रण पर निर्भर थी। स्थापना लागत का कुल लागत से अनुपात और शाखाओं का वस्तार महत्वपूर्ण कारक थे, जो उनकी व्यवहार्यता को प्रभा वत करते थे। अध्ययन ने आगे निष्कर्ष निकाला क आरआरबी को अपने सस्टम में दोषों के कारण नुकसान उठाना पड़ा, इन्हें सुधारने और उन्हें व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता थी। अध्ययन के मुख्य सुझावों में बुनियादी सु वधाओं में सुधार और वा णज्यिक बैंकों द्वारा उन क्षेत्रों में शाखाएं खोलना शा मल था जहां आरआरबी पहले से ही कार्य कर रहे थे।

वर्ष 1989 में पहली बार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संपूर्ण संरचना की अवधारणा को कृ ष ऋण समीक्षा स मति (खुसरो स मति) द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था क इन बैंकों के पास जारी रखने का कोई न्यायो चत कारण नहीं है और उन्होंने प्रायोजक बैंकों के साथ उनके वलय की सफारिश की। . स मति का वचार था क "आरआरबी की कमजोरियां प्रणाली के लए स्थानिक हैं और इसमें गैर-व्यवहार्यता अंतर्निहित है, और एकमात्र वकल्प आरआरबी को प्रायोजक बैंकों के साथ वलय करना था। कमजोर वर्गों की प्रभावी ढंग से सेवा

www.ignited.in

करने का उद्देश्य केवल आत्मनिर्भर क्रे डट संस्थानों द्वारा ही प्राप्त कया जा सकता है।"

वत्तीय प्रणा लयों पर स मति, 1991 (नर सम्हम स मति) ने आरआरबी के खराब वत्तीय स्वास्थ्य पर जोर दिया और हर दूसरे प्रदर्शन संकेतक को बाहर कर दिया। 196 आरआरबी में से 172 को 40.8 प्रतिशत के कुल ऋण वसूली प्रदर्शन के साथ लाभहीन दर्ज कया गया। (जून 1993)। इन बैंकों के कम इक्विटी आधार (25 लाख रुपये की चुकता पूंजी) ने अ धकांश आरआरबी के ऋण घाटे को कवर नहीं कया। कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में पूंजी के अलावा जनता की जमा रा श में भी कमी आई है। आरआरबी के संचालन को व्यवहार्यता प्रदान करने के लए, नर सम्हम स मति ने सुझाव दिया क आरआरबी को सभी प्रकार के बैं कंग व्यवसाय में संलग्न होने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें अपने संचालन को ल क्षत समूहों तक सी मत करने के लए मजबूर नहीं कया जाना चाहिए, एक प्रस्ताव जिसे आसानी से स्वीकार कर लया गया था। इस सफारिश ने आरआरबी के कामकाज में एक प्रमुख मोड़ दिया।

बैं कंग दक्षता पर समकालीन साहित्य दक्षता (1) लेखांकन उपाय (2) आ र्थक माप को मापने के लए दो अलग-अलग दृष्टिकोणों को बताता है।

लेखांकन उपाय व भन्न वत्तीय अनुपातों के उपयोग को संद र्भत करता है जो एक बैं कंग इकाई के प्रदर्शन को मापने के लए एक या अ धक आउटपुट और उनके प्रासं गक इनपुट पर ध्यान केंद्रित करता है। आरआरबी के प्रदर्शन का वश्लेषण करने के लए शोधकर्ताओं और कार्य समूहों / स मतियों द्वारा वत्तीय अनुपात दृष्टिकोण का व्यापक रूप से उपयोग कया गया है। आरआरबी के प्रदर्शन मूल्यांकन पर अ धकांश अध्ययन वशेष राज्य/क्षेत्र के बैंकों पर केंद्रित हैं। कुछ अध्ययन हैं: संह (1992) ने पंजाब में आरआरबी बैंकों के प्रदर्शन का वश्लेषण कया। प्रसाद (2003) ने भारत में आरआरबी के प्रदर्शन का मूल्यांकन कया। इसके अलावा, पति (2005) ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन का वकास कया। बागची और हादी (2006) का अध्ययन पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन पर केंद्रित था। साहित्य में कुछ अध्ययन भी मौजूद हैं जो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की दक्षता पर केंद्रित हैं। अब तक कए गए कुछ अध्ययन इस प्रकार हैं: सुधाकर एवं अन्य (1984) ने मैसूर जिले में कावेरी ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन कया; परमार (1986) ने गुजरात में बनासकांठा मेहसाने ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन का आकलन कया; सांगवान (1988) ने आंध्र प्रदेश में चटंज ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन का वश्लेषण कया; जगदीश और अन्य (1990) ने कर्नाटक में तुंगभद्रा ग र्मन बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन कया। इसके अलावा, होसामनी (2002) ने कर्नाटक में मालाप्रभा ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन का पता लगाया और यदप्पनवर और नाथ (2003) ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद और जालना ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन का आकलन कया। हालां क वत्तीय लेखा अनुपात का उपयोग करना आसान है और समझने में अपेक्षाकृत आसान है, ले कन बैंक के प्रदर्शन को मापने के लए उनका उपयोग व भन्न समस्याओं से ग्रस्त है। एहतियाती उपाय के रूप में, दुनिया भर में अ धकांश पर्यवेक्षी प्रणा लयों में इन अनुपातों पर आधारित वनियामक ढांचा (जैसे CAMEL रेटिंग) स्था पत कया गया है। इसके अलावा, शर्मन और गोल्ड (1985) ने कहा क वत्तीय अनुपात लंबी अव ध के प्रदर्शन पर कब्जा नहीं करते हैं। यह उपाय समग्र दक्षता स्तर निर्धारित करने वाले अलग-अलग मापदंडों के संदर्भ में बैंक के प्रदर्शन के वश्लेषण में भी मदद करता है क्यों क बैंकों की दक्षता को ठीक से मापना मुश्किल है।

अध्ययन का उद्देश्य

- भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वत्तीय प्रदर्शन को मापने के लए।
- भारत में आरआरबी के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का वश्लेषण करना
- 2006-05 से 2015-11 के दौरान आरआरबी की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वकास-पैटर्न का अध्ययन करना।
- आरआरबी के कामकाज में सुधार के लए महत्वपूर्ण सुझाव देना।

अनुसंधान क्रया व ध

भारत में आरआरबी के वत्तीय प्रदर्शन का वश्लेषण प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की मदद से कया गया है। वकास दर की गणना के लए वर्ष 2015-2020 को चालू वर्ष तथा वर्ष 2009-2010 को आधार वर्ष माना गया। नियोजित वश्लेषणात्मक तकनीकें- आरआरबी से संब धत वत्तीय प्रदर्शन का अध्ययन करने की दृष्टि से वकास दर

www.ignited.in

वश्लेषण कया गया था। वकास दर को निम्न सूत्र की सहायता से मापा जाता है-

Growth Rate = Yt -Yt-1 / Yt-1

Yt= चालू वर्ष, yt-1= आधार वर्ष.

अनुसंधान डजाइन

वर्तमान अध्ययन प्रकृति में नैदानिक और खोजपूर्ण है और द् वतीयक डेटा का उपयोग करता है। यह अध्ययन 2006-07 से शुरू होकर 2010-11 तक 5 साल की अव ध के लए केवल व शष्ट क्षेत्रों जैसे क शाखाओं की संख्या, जिला कवरेज, जुटाई गई जमा रा श, क्रे डट और भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा कए गए निवेश तक ही सी मत है।

डेटा संग्रह की व ध

वर्तमान अध्ययन वश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित चरित्र में अनुभवजन्य है। अध्ययन मुख्य रूप से द् वतीयक डेटा पर आधारित है जो मुख्य रूप से नाबार्ड और आरबीआई की वा र्षक रिपोर्ट से एकत्र, संक लत और गणना की जाती है। पत्रिकाओं, सम्मेलन की कार्यवाही और वेबसाइटों से एकत्रित अन्य संबं धत जानकारी।

प्रमुख प्रदर्शन संकेतक और आरआरबी का वकास

ता लका 1 वर्ष 2006-07 से आरआरबी के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक और वकास को प्रस्तुत करता है 2010-2011,

ता लका **1.** भारत में आरआरबी के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक

(रु. करोड़ में)

पैरामीटर	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	विकास
आरआरबी की संख्या	96	91	86	82	82	---
लाभ/हानि बनाना	81/15	83/8	80/6	79/3	75/7	---
शाखाओं की संख्या	14526	14761	15158	15480	16001	3.36
ज़िलों को कवर किया गया	534	594	617	618	620	0.32
कर्मचारी	68289	68005	68509	69042	70153	1.61
स्वामित्व निधि	7285.98	8732.59	10895.73	12247.16	13838.92	13.00
जमा	83143.55	99093.46	120184.46	145035.00	166232.34	14.60
उधारी	9775.80	11494.00	12733.80	18770.00	26490.81	41.10
निवेश	45666.14	48559.54	62629.45	79379.16	86510.44	8.98
सकल ऋण (O/s)	48492.59	58984.27	67858.48	82819.10	98917.43	19.14
ऋण जारी	33043.49	38581.97	43445.59	56079.24	71724.19	27.90
सीडी अनुपात	58.32	59.52	56.46	57.10	59.51	---
संचित घाटा	2759.49	2624.22	2325.59	1775.06	1532.39	- 13.67
कर देने से पूर्व लाभ	926.40	1383.68	1859.36	2514.83	2420.75	- 3.74
नुकसान	301.25	55.58	35.91	5.65	71.32	1162.30
सरकार को भुगतान किया गया कर।	139.66	301.12	461.14	625.25	634.22	1.44
सकल एनपीए	3178.01	3566.34	2804.02	3084.82	3712.00	20.32
सकल एनपीए %	6.55	6.05	4.13	3.72	3.75	---
शुद्ध एनपीए राशि	1625.41	1929.71	1114.54	1423.31	1941.32	36.39
नेट एनपीए %	3.46	3.19	1.68	1.80	2.05	---
वसूली %	79.80	80.84	77.76	80.09	81.18	---
निवल मूल्य	4526.48	6107.37	8570.04	10472.10	12306.53	17.52
शाखा उत्पादकता	9.06	10.75	12.41	14.72	16.57	12.57
कर्मचारी उत्पादकता	1.93	2.33	2.74	3.70	3.78	2.16

1. स्वा मत्व नि ध

31 मार्च 2011 को 31 मार्च 2011 को 12247.16 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2011 को शेयर पूंजी, शेयरधारकों से प्राप्त शेयर पूंजी जमा और रिजर्व सहित 13838.92 करोड़ पर आरआरबी के स्वा मत्व वाली नि ध; 13.0% की वृद् ध दर्ज की। 1591.76 करोड़ की स्वा धकृत नि धयों में वृद् ध मुख्य रूप से लाभ कमाने वाले आरआरबी द्वारा भंडार में वृद् ध के कारण थी। शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा मलाकर कुल स्वा धकृत नि ध का 4273 करोड़ था जब क शेष रा श 9566 करोड़ आर क्षत रा श का प्रतिनि धित्व करती थी।

2. जमा

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमारा श 14.60% की वृद् ध दर दर्ज करते हुए 145035 करोड़ से बढ़कर 166232.34 करोड़ हो गई। गुड़गांव जीबी ने 37% की उच्चतम जमा वृद् ध दर दर्ज की। सोलह (16) आरआरबी हैं जिनमें से प्रत्येक में 3000 करोड़ से अ धक की जमा रा श है।

3. उधार

आरआरबी का उधार 31 मार्च 2010 को 18770 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2011 को 26490.81 करोड़ हो गया, जिसमें 41.10% की वृद् ध दर्ज की गई। पछले वर्ष के 22.7% की तुलना में बकाया सकल ऋण की तुलना में उधारी 26.8% थी।

धन का उपयोग

www.ignited.in

आरआरबी के धन के उपयोग में निवेश और ऋण और अ ग्रम शा मल हैं.

4. निवेश

आरआरबी का निवेश 31 मार्च 2010 को 79379.16 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2011 को 86510.44 करोड़ हो गया, जो 8.98% की वृद् ध दर्ज करता है। एसएलआर निवेश की रा श ₹ 45022 करोड़ थी जब क गैर-एसएलआर निवेश ₹ 41488 करोड़ था। आरआरबी का निवेश जमा अनुपात (आईडीआर) 31 मार्च 2011 को 31.3.2001 को 72% से धीरे-धीरे घटकर 52.04% हो गया।

5. ऋण और अ ग्रम

वर्ष के दौरान बकाया ऋण 16098.33 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2011 को 98917.43 करोड़ हो गया, जो पछले वर्ष की तुलना में 19.4% की वृद् ध दर दर्ज करता है। मेघालय ग्रामीण बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 35% की उच्चतम वृद् ध दर दर्ज की।

6. जारी कए गए ऋण

वर्ष के दौरान आरआरबी द्वारा जारी कुल ऋण पछले वर्ष के दौरान 56079.24 करोड़ से बढ़कर 27.90% की वृद् ध दर्ज करते हुए 71724.19 करोड़ हो गया। समस्तीपुर केजीबी ने 2010-11 के दौरान 123% की उच्चतम वृद् ध दर दर्ज की, जिसके बाद आंध्र प्रदेश जीवीबी 112% पर रहा।

कार्य परिणाम

1. लाभप्रदता

वर्ष 2010-2011 के दौरान 75 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से) ने 2420.75 करोड़ की सीमा तक लाभ (कर से पहले) अर्जित कया है। लाभ पछले वर्ष की तुलना में मामूली कम था। 634.22 करोड़ के आयकर के भुगतान के बाद शुद्ध लाभ 1786.53 करोड़ हो गया। शेष 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ₹ 71.32 करोड़ की हानि हुई।

2. सं चत घाटा

31 मार्च 2011 तक, 31 मार्च 2010 को 1775.06 करोड़ (27 आरआरबी) की तुलना में 31 मार्च 2011 को 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 23 का संचयी घाटा 1532.39 करोड़ रहा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सं चत घाटा 242.67 करोड़ घट गया।

3. अनर्जक आस्तियां (एनपीए)

31.03.2011 को आरआरबी का सकल एनपीए 3712 करोड़ था (यानी 3.75%)। वर्ष के दौरान आरआरबी के शुद्ध एनपीए के प्रतिशत में 1.8% से 2.05% की वृद् ध देखी गई है। आंकड़ों से पता चला क 15 आरआरबी का सकल एनपीए प्रतिशत 2% से कम था, जब क 33 आरआरबी का यह 5% से अ धक था।

4. रिकवरी प्रदर्शन

30 जून 2009 को 80.09% से 30 जून 2010 को 81.18% तक 2009-10 के दौरान वसूली प्रतिशत में सुधार हुआ है। कुल बकाया, हालां क, 30 जून 2010 को 934 करोड़ से बढ़कर 9805 करोड़ हो गया।

5. क्रे डट जमा अनुपात

आरआरबी का कुल सीडीआर 31 मार्च 2010 को 57.10% से बढ़कर 31 मार्च 2011 को 59.51% हो गया। आठ आरआरबी ने 100% से अ धक सीडीआर की सूचना दी।

6. शाखा और कर्मचारियों की उत्पादकता

शाखा उत्पादकता 12.57% की वृद् ध के साथ 2009-10 में 14.72 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में 16.57 करोड़ हो गई। इसी तरह, 2010-11 में कर्मचारियों की उत्पादकता 2.16% की वृद् ध के साथ 2009-10 में 3.70 करोड़ से बढ़कर 3.78 करोड़ हो गई।

वर्ष **2010-2011** के दौरान नीतिगत पहलें

1. सीआरएआर में सुधार के लए पूंजी प्रवाह

आरआरबी की दिनांक 18.08.2009 की वत्त मंत्री की समीक्षा बैठक में लए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, डॉ. के.सी. की अध्यक्षता में भारत सरकार, वत्त मंत्रालय, वत्तीय सेवा वभाग द्वारा एक स मति गठित की गई थी। चक्रवर्ती, डप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, को सीआरएआर के संदर्भ में आरआरबी की वत्तीय स्थिति की जांच करने और मार्च 2012 तक 9% का सीआरएआर हा सल करने के लए रोडमैप सुझाने के लए कहा गया है। डॉ. के.सी. चकरबर्ती स मति की रिपोर्ट 21 राज्यों में 40 चयनित आरआरबी को पुनर्पूंजीकरण 2010-11 में

www.ignited.in

शुरू कया गया था। पुनर्पूंजीकरण रा श को हितधारकों द्वारा उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अर्थात 50%, 35% और 15% केंद्र सरकार, संबं धत प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकार द्वारा साझा कया जाना है। अनुमोदित योजना के अनुसार, केंद्र सरकार के हिस्से की रिहाई केंद्र सरकार, संबं धत प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक हिस्सेदारी के अधीन है। 2010-11 के दौरान 5 आरआरबी को 66.49 करोड़ की रा श जारी की गई थी।

स मति की सफारिशों को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने अन्य शेयरधारकों के साथ 2200 करोड़ की सीमा तक धनरा श लगाकर आरआरबी को पुनर्पूंजीकृत करने का निर्णय लया। कार्यान्वयन पहले से ही चल रहा है और 2012-13 के दौरान पूरा होने की उम्मीद है।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सेवा वनियम **2010**

अमरेश कुमार स मति की सफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने आरआरबी सेवा वनियम 2010 जारी कया।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमावली **2010**

भारत सरकार ने जुलाई 2010 में आरआरबी नियुक्ति और पदोन्नति नियम 2010 को भी अ धसू चत कया।

4. कोर बैं कंग सॉल्यूशंस **(CBS)** के माध्यम से प्रौद्यो गकी नवाचार

आरआरबी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी क उनकी शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर रखी जाएं ता क वे अपने ग्राहकों को परेशानी मुक्त और कहीं भी बैं कंग सेवाएं प्रदान कर सकें। 30 सतंबर 2011 को 80 आरआरबी को पूरी तरह से सीबीएस में स्थानांतरित कर दिया गया है। नाबार्ड वत्तीय समावेशन प्रौद्यो गकी नि ध (एफआईटीएफ) से कोर बैं कंग समाधान के लए 40% की सीमा तक पहचाने गए 28 कमजोर आरआरबी को वत्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और शेष लागत होगी प्रायोजक बैंक (50%) और आरआरबी (10%) द्वारा साझा कया गया

5. वत्तीय समावेशन

जैसा क भारत सरकार द्वारा परिकल्पित कया गया है, आरआरबी एक समूह के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बड़ी संख्या में "नो फ्रल्स" खाते खोलकर और सामान्य क्रे डट कार्ड (जीसीसी) के तहत वत्तपोषण करके ग्रामीण क्षेत्रों में वत्तीय समावेशन के लए एक मजबूत मध्यस्थ बन गए हैं। मार्च 2011 में खातों की कुल संख्या 1310.17 लाख थी जो मार्च 2010 में 1188.67 लाख थी।

6. आरआरबी को ब्याज सबवेंशन

केंद्रीय बजट 2010-11 में ब्याज सबवेंशन योजना को जारी रखने की घोषणा की गई थी। प्रति कसान 3 लाख रुपये तक के फसली ऋण के लए अपने स्वयं के धन को लगाने के लए आरआरबी को 1.5% प्रति वर्ष का ब्याज सबवेंशन उपलब्ध था, बशर्ते क अंतिम उधारकर्ता को प्रति वर्ष 7% ब्याज पर ऐसा ऋण मले। वर्ष के दौरान उन कसानों के लए 2% की अतिरिक्त छूट की घोषणा की गई, जिन्होंने सं वतरण के एक वर्ष के भीतर तुरंत फसल ऋण चुका दिया। इस प्रकार, ऐसे कसानों द्वारा फसल ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज प्रभावी रूप से 5% की दर से था।

आरआरबी की समस्याएं (कमजोरी)।

हालां क क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा नेटवर्क का तेजी से वस्तार हुआ और व्यापार की मात्रा में वृद्ध हुई, इन संस्थानों को निम्न ल खत समस्याओं के कारण एक बहुत ही कठिन वकासवादी प्र क्रया से गुजरना पड़ा।

1. संचालन का बहुत सी मत क्षेत्र
2. केवल ल क्षत समूह के संपर्क में आने के कारण उच्च जो खम
3. जनता की धारणा है क आरआरबी गरीब आदमी के बैंक हैं
4. संसाधन-गरीब क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में संचालन के गैर-व्यवहार्य स्तर के कारण बढ़ते नुकसान।
5. टर्न-ओवर रणनीति के रूप में संकीर्ण निवेश बैं कंग पर स्विच करें
6. प्रायोजक बैंकों से सौतेले व्यवहार को छोड़कर, कम रिटर्न वाले निवेश के अवसरों के लए प्रायोजक बैंकों पर भारी निर्भरता।
7. प्रायोजक बैंकों द्वारा निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त क्षेत्रीय प्रबंधकों के निर्देशन में आरआरबी

www.ignited.in

के अध्यक्ष

8. सरकारी सब्सिडी योजनाओं का बोझ और ग्राहकों की अपर्याप्त जानकारी के कारण कम गुणवत्ता वाली संप त्त

9. लाभ उन्मुखीकरण और कार्यात्मक दक्षता के प्रति कम प्रतिबद्धता वाले संघबद्ध कर्मचारी।

10. लाभ उन्मुखीकरण के लए ट्रेजरी प्रबंधन में अपर्याप्त कौशल

11. ऋण देने वाले पोर्टफो लयो को सी मत करने वाले उत्पादों को नया करने के लए अपर्याप्त जो खम और कौशल

12. एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मामलों और व्यवसाय के प्रबंधन के लए कर्मचारियों की क्षमता में उत्कृष्टता के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लए अपर्याप्त प्रयास

13. अ धकांश निर्णयों के लए प्रायोजक बैंकों, भारत सरकार, नाबार्ड और आरबीआई की ओर देखने की बाध्यता द्वारा बोर्ड को गंभीर रूप से कमजोर करना।

14. कर्मचारियों की भर्ती पर बोर्ड के प्रतिबंध से आरआरबी बा धत।

निष्कर्ष

निष्कर्ष निकालने के लए, आरआरबी के तेजी से वस्तार ने भारत में बैं कंग सु वधाओं के संबंध में क्षेत्रीय वषमताओं को काफी हद तक कम करने में मदद की है। शाखा वस्तार, जमा संग्रहण, ग्रामीण वकास और ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग में ऋण परिनियोजन में आरआरबी द्वारा कए गए प्रयास सराहनीय हैं। आरआरबी सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है जैसे ग्रामीण परिवारों के दरवाजे तक बैं कंग ले जाना, वशेष रूप से बैं कंग से वं चत ग्रामीण क्षेत्र में, कमजोर ग्रामीण वर्ग के लए आसान और सस्ता ऋण प्राप्त करना, जो निजी उधारदाताओं पर निर्भर हैं, उत्पादक गति व धयों के लए ग्रामीण बचत को प्रोत्साहित करना, रोजगार पैदा करना ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्राप्त करने की लागत को कम करने के लए। इस प्रकार आरआरबी सबसे मजबूत बैं कंग नेटवर्क प्रदान कर रहा है। ग्रामीण बैंकों को व्यवहार्य बनाने के लए सरकार को कुछ प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। कृ ष, व्यापार और उद्योग के वकास के लए छोटे, सीमांत कसानों और जनसंख्या के सामाजिक आ र्थक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण वतरण के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वतरण के एक महत्वपूर्ण वाहन के रूप में महत्वपूर्ण भू मका निभाते हैं। ले कन फर भी इसकी व्यावसायिक व्यवहार्यता इसके सी मत व्यापार लचीलेपन, ऋण के छोटे आकार और ऋण और अ ग्रमों में उच्च जो खम के कारण पूछताछ की गई है। ग्रामीण बैंकों को अपने संचालन में पारद र्शता की कमी को दूर करने की आवश्यकता है जो बैंकर और ग्राहक के बीच असमान संबंध की ओर ले जाता है। इस समस्या को दूर करने के लए बैं कंग कर्मचारियों को अपने ग्राहकों से अ धक बातचीत करनी चाहिए। बैंकों को अपनी शाखाएं उन क्षेत्रों में खोलनी चाहिए जहां ग्राहक बैं कंग सु वधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धी युग में, आरआरबी को मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने और संभा वत ग्राहकों को आक र्षत करने के लए तेज, गुणात्मक और सुर क्षत बैं कंग सेवाओं पर ध्यान देना होगा.

संदर्भ

1. बगाची, के.के. और ए. हादी (2006), पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन: एक मूल्यांकन, सीरियल प्रकाशन: नई दिल्ली।

2. बोस, एस. (2005) रीजनल रूरल बैंक्स: द पास्ट एंड द प्रेजेंट डबेट

3. दास, यू.आर. (1998) "प्रदर्शन और आरआरबी की संभावनाएं", बैं कंग वत्त नवंबर।

4. गुप्ता, एस.के. (1996) "प्रॉ फटेबि लटी एंड रीजनल रूरल बैंक्स", कुरुक्षेत्र, जुलाई।

5. गुप्ता और सोढ़ी (1995), "इकोनॉ मक लबरलाइजेशन एंड रूरल क्रे डट", कुरुक्षेत्र, वॉल्यूम। XLIII, नंबर 10, पी-27-30

6. हॉर्समैन, एस.बी (2002), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन, नई दिल्ली,

7. इब्राहिम डॉ. एम. सैयद (2010) "भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन मूल्यांकन", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान वॉल्यूम। 3, नंबर 4; पी-203-211

8. झम पूनम (2012) "बैं कंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड

www.ignited.in

प्रोग्रेस ऑफ़ रीजनल रूरल बैंक्स इन इं डया (एन एना लटिकल स्टडी)", ऑनलाइन प्रका शत 11 जनवरी।

9. खानखोजे, डी. और सत्ये, एम. (2008) "ग्रामीण बैंकों की दक्षता: भारत का मामला", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान, वॉल्यूम। 1. नंबर 2, पीपी। 140-149।

10. कन्नन, आर. (2004), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

11. मश्रा, बी.एस. (2006), "भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन: भ वष्य के लए सुझाव देने के लए अतीत कुछ भी है", आरबीआई समसामयिक पत्र, खंड 27, संख्या 1 और 2

12. मोहिंद्रा वर्शा और कौर डॉ. जियान, टोटल फैक्टर प्रोडक्टि वटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इं डया: ए माल्मक्विस्ट एप्रोच, अ भनव जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वॉल्यूम 1 अंक 3, पी-75-86

13. मोहिंद्रा वर्शा और कौर जियान (2012) रीजनल रूरल बैंक्स इन इं डया संस रिफॉर्म्स: ए स्टडी ऑफ टेक्निकल ए फ शएंसी, प्रेरणा, मार्च।

14. प्रसाद, टी.एस. (2003), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: प्रदर्शन मूल्यांकन, कुरुक्षेत्र, वॉल्यूम। 51, नंबर 10, पी। 20-24।

15. संघा, कन्हैया (1990) "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन", कुरुक्षेत्र, 38 (10): 9-11।

Corresponding Author

Rakesh Meena*

Research Scholar, University of Rajasthan